दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, रविवार, 27 मार्च 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 177

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

महत्वपूर्ण एवं खास

युगांडा का व्यक्ति आईजीआई में 5.9 करोड़ रुपये की हेरोइन के साथ गिरफ्तार

नई दिल्ली (आरएनएस)। युगांडा के एक नागरिक को यहां आईजीआई हवाईअड्डे पर 5.9 करोड़ रुपये मूल्य की हेरोइन की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सीमा शुल्क के एक अधिकारी ने कहा कि उस व्यक्ति को हवाई अड्डे पर संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया था। बाद में उसके पास से 843 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। वह हेरोइन को कैप्सूल के रूप में तस्करी करने की कोशिश कर रहा था। सीमा शुल्क अधिकारी ने कहा, चिकित्सीय निगरानी में रखे जाने के बाद, उसने कुल 85 कैप्सूल निकाले। अधिकारी ने कहा कि उस व्यक्ति ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन किया था, और अधिनियम की धारा 21, धारा 23 और धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध किया। सीमा शुल्क अधिकारियों ने बाद में उसे अदालत में पेश किया और अदालत से उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की। अदालत ने उनकी दलीलें सुनने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बाद में उसे तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। अधिकारी ने बताया कि मामले में आगे की जांच की जा रही है।

ट्यूशन टीचर ने छात्रा को जबरदस्ती दिखाया पॉर्न, टीचर पर मामला हुआ दर्ज

जींद (आरएनएस)। हरियाणा के जींद में ट्यूशन टीचर की बहुत ही शर्मनाक हरकत सामने आई है। जिला पुलिस ने टीचर के खिलाफ पढ़ाई के बीच छात्रा को जबरन पॉर्न दिखाने का मामला दर्ज किया है। टीचर पर छात्रा के पिता की हत्या करने की धमकी देने का मामला भी दर्ज हुआ है। पीड़िता से मिली शिकायत के आधार पर महिला थाना पुलिस ने बताया कि छात्रा अंकुर नामक व्यक्ति के पास ट्यूशन पढने जाती थी। उन्होंने बताया कि अंकुर ने घर में ट्यूशन पढ़ाने के दौरान छात्रा को जबरन पॉर्न वीडियो दिखाया। छात्रा ने घर जाकर माता-पिता से इसकी शिकायत की। इसके बाद छात्रा ने ट्यूशन जाना बंद कर दिया। छात्रा ने ट्यूशन जाना किया बंद शिकायत के अनुसार, घटना के बाद छात्रा ने जब ट्यूशन जाना बंद कर दिया तो अंकुर उसका पीछा करने लगा। एक दिन अंकुर ने उसके पिता की गाड़ी के आगे बाइक लगाकर जान से मारने की धमकी भी दी। इसकी शिकायत पुलिस थाने में की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी फिलहाल फरार है, जिसकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है।

पीएम एक अप्रैल को छात्रों, उनके माता-पिता और शिक्षकों से परीक्षा पे करेंगे चर्चा

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक अप्रैल, 2022 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाली परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, उनके माता-पिता और शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। वे तनाव-मुक्त परीक्षाओं पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है: आईये, एक बार फिर तनाव-मुक्त परीक्षाओं पर बात करते हैं! ऊर्जावान ग़्एक्ज़ाम-वॉरियर्स, उनके माता-पिता और शिक्षकों को एक अप्रैल को इस वर्ष की परीक्षा पे चर्चा में हिस्सा लेने का आह्वान।

पीएम ने आयुष मंत्रालय द्वारा डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए समझौते का स्वागत किया

नई दिल्ली(आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को लेकर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह केंद्र धरती को स्वस्थ बनाने और वैश्विक हित में हमारी समृद्ध पारम्परिक विधियों के दोहन बनाने में अपना योगदान करेगा। आयुष मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ ने केंद्र के लिए एक मेजबान देश समझौता किया। प्रधानमंत्री ने आयुष मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ के ट्वीट्स का उत्तर देते हुए यह बात कही। प्रधानमंत्री ने टवीट करते हुए कहा भारत अपने यहां अत्याधुनिक डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को लेकर खासा सम्मानित महसूस कर रहा है। यह केंद्र एक स्वस्थ ग्रह के निर्माण और वैश्वित हित के लिए हमारी समृद्ध पारंपरिक विधियों के दोहन की दिशा में योगदान करेगा।

रक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 से साझेदारी मोड में 21 नए सैनिक स्कूलों को मंजूरी दी

नई दिल्ली (आरएनएस)। रक्षा मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों/निजी स्कूलों/राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में 21 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दी है। ये स्कूल देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल पार्टनरशिप मोड में स्थापित करने की सरकार की पहल के शुरुआती दौर में स्थापित किए जाएंगे। वे विद्यमान सैनिक स्कूलों से अलग होंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना के विजन का उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने सहित करियर के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। यह निजी क्षेत्र को आज के युवाओं को कल के जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए परिष्कृत करने के द्वारा राष्ट्र निर्माण की दिशा में सरकार के साथ मिलकर काम करने का अवसर भी प्रदान करता है।

21 अनुमोदित नए सैनिक स्कूलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची संलग्न है और इसे पर भी देखा जा सकता है। इनमें से 17 स्कूल ब्राउनफील्ड संचालित स्कूल हैं और 4 ग्रीनफील्ड स्कूल हैं जो शीघ्र ही प्रचालनगत होने वाले हैं। जहां गैर सरकारी संगठनों/ट्रस्ट/सोसाइटियों के पास 12 अनुमोदित नए स्कूलों की हिस्सेदारी है, 6 निजी स्कूल और 3 राज्य सरकार के स्वामित्व वाले स्कूलों ने ऐसे अनुमोदित नए सैनिक स्कूलों की सूची में जगह पायी हैं। विद्यमान सैनिक स्कूलों के विपरीत, जो विशुद्ध रूप से आवासीय प्रकृति के हैं, 7 नए सैनिक स्कूल डे स्कूल हैं और ऐसे 14 नए अनुमोदित स्कूलों में आवासीय व्यवस्था है।

ये नए सैनिक स्कूल, संबंधित शिक्षा बोर्डों से संबद्धता के अतिरिक्त, सैनिक स्कूल सोसायटी के तत्वावधान में कार्य करेंगे और सोसायटी द्वारा निर्धारित साझेदारी मोड में नए सैनिक स्कूलों के लिए नियमों और विनियमों का पालन करेंगे। अपने नियमित संबद्ध बोर्ड पाठ्यक्रम के अलावा, वे सैनिक स्कूल पैटर्न के छात्रों को अकादमिक प्लस पाठ्यक्रम की शिक्षा भी प्रदान करेंगे। इन स्कूलों के संचालन के तौर-तरीकों से संबंधित विवरण बेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इच्छुक छात्रों और अभिभावकों को वेब पोर्टल पर जाने और इस नए अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

नामांकन प्रक्रिया:

इन स्कूलों में नए सैनिक स्कूल पैटर्न में प्रवेश कक्षा स्तर पर केवल निम्नलिखित तरीके से होगा।

छठी कक्षा में कम से कम 40 प्रतिशत प्रवेश उन उम्मीदवारों का होगा जिन्होंने ई काउंसलिंग के माध्यम से एनटीए द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है।

60 प्रतिशत तक प्रवेश उसी स्कूल में नामांकित और नए सैनिक स्कूलों के इस वर्टिकल के तहत योग्यता परीक्षा के माध्यम से प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों का होगा, जिसके लिए अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी।

अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा-2022 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को एनटीए के साथ उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर नए अनुमोदित सैनिक स्कूल खोलने और इन स्कूलों में आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जा रहा है। ऐसे योग्य उम्मीदवार जो अपनी पसंद के नए अनुमोदित स्कूल में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं, उन्हें पूर्व परामर्श पोर्टल् पर पंजीकृत करना होगा। छात्रों को वेब पोर्टल पर लॉग इन करने और पंजीकरण करने के लिए अपने एआईएसएसईई-2022 आवेदन संख्या का उपयोग करना होगा जिसके बाद आवेदक छात्र ई-परामर्श के लिए प्राथमिकता के क्रम में 10 स्कूलों तक की पसंद का संकेत दे सकता है। पंजीकृत आवेदकों को प्रत्येक स्कूल के लिए मेरिट सूची के क्रम में एआईएसएसईई 2022 योग्य उम्मीदवारों द्वारा उस स्कूल में भरी जाने वाली सीटों की सीमा तक स्कूल आवंटित किए जाएंगे। नए सैनिक स्कूलों में शामिल होने के इच्छुक एआईएसएसईई 2022 के योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ई-परामर्श पर सभी नवीनतम अपडेट के लिए नियमित रूप से वेब पोर्टल देखें।

नए सैनिक स्कूल में पहले से नामांकित और नए सैनिक स्कूलों के इस वर्टिकल के तहत पढने के इच्छुक छात्रों को शीघ्र ही आयोजित होने वाली योग्यता परीक्षा के आधार पर प्रवेश प्रदान किया जाएगा। नए सैनिक स्कूलों को इसके बारे में अलग से अधिसूचित किया जा रहा है ताकि ऐसे इच्छुक उम्मीदवारों का विवरण, निर्धारित समय सीमा के भीतर, परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी को प्रदान किया जा सके, जिसका विवरण वेब पोर्टल पर भी उपलब्ध होगा।

सितंबर तक पूरा होगा चिनाब नदी पर बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण : मनोज

जम्मू (आरएनएस)। चिनाब नदी पर जारी दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण इस साल सितंबर में पूरा हो जाएगा। इस बात की जानकारी जम्मू और कशअमीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दी है। यह पुल कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ेगा। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के जल्दी ही दोगुना होने की उम्मीद जताई है। सिन्हा ने कहा कि केंद्र ने क्षेत्र के विकास, समृद्धि और प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए 2019 से जम्मू और कश्मीर के बजट को दोगुना किया है। जम्मू में आयोजित प्रेस मीट को संबोधित करते हुए जम्मू और कश्मीर को आवंटित हुए 1.12 लाख करोड़ रुपये के वार्षिक बजट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने क्षेत्र के आर्थिक विकास में तेजी आने की बात कही है।

उन्होंने कहा, इस साल सितंबर में चिनाव नदीं पर सबसे ऊंचा रेलवे पुल तैयार हो जाएगा और कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा... अगस्त 2019 से क्षेत्र के विकास की रफ्तार दोगुनी हो गई है। उन्होंने बताया कि जम्मू और कश्मीर को आवंटित हुआ बजट को बगैर किसी भेदभाव के 1.30 करोड़ लोगों पर खर्तच किया जाएगा। उन्होंने कहा, यह बजट लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करेगा। यह पुल 1.315 किमी लंबा होगा और नदी जल स्तर से 359 मीटर ऊंचा होगा। खास बात है कि इसकी लंबाई पेरिस में स्थित एफिल टॉवर से भी 35 मीटर ज्यादा होगी। इसके निर्माण में 28 हजार 660 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है।

महंगाई के खिलाफ 31 मार्च को सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, देशव्यापी आंदोलन का ऐलान

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस के महासचिव व प्रभारियों की बैठक शनिवार को बैठक बुलाई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 31 मार्च को महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन होगा। थाली बजाओ, महंगाई भगाओ नारा दिया गया। कई घण्टे चली इस बैठक में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, उत्तरप्रदेश महासचिव प्रियंका गांधी, कर्नाटक महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, अविनाश पांडेय, पीएल पूनियां, हरीश चौधरी, अजय माकन, शकयी सिंह गोहिल, तारिक अनवर, अजॉय कुमार सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे।

वहीं बैठक को लेकर उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस महासचिव एवं राज्य के प्रभारियों की बैठक में सदस्यता अभियान एवं जनता के मुद्दों पर आंदोलन की चर्चा में अपने विचार रखें। बैठक में निर्णय लिया गया कि 31 मार्च को महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन होगा। थाली बजाओ,महंगाई भगाओ नारा दिया गया। इसके साथ ही 2-4 अप्रैल को ब्लॉक व जिला स्तर पर प्रदर्शन होगा। साथ ही 7 अप्रैल को प्रदेश की राजधानी में प्रदर्शन होगा।

कांग्रेस के सभी राज्यों के प्रभारियों ने इस बैठक में अपने राज्यों की रिपोर्ट सौंपी। ये रिपोर्ट और बैठक खासतौर पर चुनावी राज्यों के प्रभारी और जिन 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की हार हुई है। दरअसल कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी 26 मार्च को पार्टी के महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों के साथ एक बैठक कर मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने की।

कांग्रेस मुख्यालय में हुई बैठक में सभी राज्यों के प्रभारी अपनी-अपनी फीडबैक रिपोर्ट बनाने में जुट गए हैं। उत्तराखंड, पंजाब, उत्तरप्रदेश, मणिपुर और गोवा में कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा उसके बाद इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि जल्द ही इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी नय प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति होगी।

दरअसल इन सबके बीच पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी हालात पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने पार्टी नेताओं से मौजूदा हालात को लेकर एक बैठक करने को कहा था। माना जा रहा है उसके आधार पर प्रदेश में नय अध्यक्ष की नियुक्ति और संगठन में फेरबदल किये जायेंगे। हालांकि शनिवार को हुई इस बैठक से पहले हरियाणा के भी तमाम नेताओं ने शुक्रवार को दिल्ली पहुंचक राहुल गांधी से मुलाकात की।

अमित शाह ने 110 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया

नई दिल्ली (आरएनएस)। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में अन्नक्षेत्र और नवनिर्मित कॉलेज ऑफ ऑडियोलॉजी सहित अनेक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अमित शाह ने मोटी भोयण (कलोल) में कैंसर जागरूकता अभियान का शुभारंभ भी किया। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कलोल टाउन हॉल के निकट रेलवे ओवर ब्रिज का शिलान्यास भी किया। अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज कलोल विधानसभा क्षेत्र में 22 करोड़ रुपये से अधिक के 110 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। हालांकि मूल्य की दृष्टि से ये विकास कार्य बहुत छोटे-छोटे दिखते हैं परंतु इन कार्यों से आज 34 गाँवों के लोगों की छोटी छोटी तकलीफ़ों का निवारण हो रहा है। अमित शाह ने कहा कि पाँच राज्यों में चुनाव होने की वजह से उन्हे बहुत समय बाद कलोल आने का अवसर मिला है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इन चुनावों में चार राज्यों में हमारी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। यह प्रचंड विजय देश की जनता के मोदी जी पर अटूट विश्वास और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही केन्द्र सरकार की नीतियों,रीतियों और कार्यक्रमों की जनस्वीकृति की परिचायक है। साथ ही यह प्रचंड विजय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भारत को पूरी दुनिया में सुरक्षित,समृद्ध और यशस्वी बनाने के लिए जारी अभियान पर जनता की मोहर है। अमित शाह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी जी ने 7 अक्तूबर 2001 से, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में यह यात्रा शुरू की और आज तक यह यात्रा अविरत रूप से निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि मोदी जी नए विचारों,योजनाओं और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए रोज 24 में से 18 घंटे काम करते हैं। शाह ने कहा कि मैंने मोदी जी को नज़दीक से काम करते देखा है वे बिना किसी अवकाश के शनिवार और रविवार सहित सातों दिन अहर्निश रूप से भारत की जनता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं और इसी वजह से चार राज्यों में हमारी पार्टी को प्रचंड लोकप्रियता मिली है। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी जी ने गुजरात के विकास में सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशक विकास की एक नई कल्पना शुरू की। विकास हर व्यक्ति तक पहुँचे और हर विस्तार का उसमे समावेश हो। उन्होंने कहा कि पहले गुजरात में शाम होते ही बिजली गुल हो जाती थी लेकिन नरेन्द्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार गाँवों में 24 घंटे बिजली पहुँचाकर देशभर को आश्चर्यचकित कर दिया था। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में संपूर्ण समस्याओं का निवारण कर आयुष्मान भारत योजना शुरू की है जिसके तहत देश के गरीब और अमीर,शहरी या ग्रामीण,प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य की चिंता भारत सरकार करती है। अमित शाह ने कहा कि देशभर में करोड़ों गरीब लोगों को आयुष्मान भारत योजना कार्ड दिए गए हैं और आज नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार उनके इलाज का पाँच लाख रूपये तक का खर्च वहन करती है।

रूस-यूक्रेन युद्ध से तेल की कीमतों में हुआ इजाफा : गडकरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले चार दिनों में ईंधन की कीमतों में तीन बार की गई बढ़ोतरी को सही ठहराते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिति भारत सरकार के नियंत्रण से बाहर है। सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी ने यहां एबीपी नेटवर्क के सम्मेलन आइडियाज ऑफ इंडिया में न्यू इंडिया, न्यू मेनिफेस्टो-सबका साथ, सबका विकास सत्र में यह भी कहा कि, कभी-कभी हिंदुत्व को गलत तरीके से पेश किया जाता है।

जब उनसे पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, भारत में 80 प्रतिशत तेल आयात किया जाता है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं।

मंत्री ने कहा कि हम 2004 से भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रहे हैं, जिसके साथ हमें स्वदेशी ऊर्जा उत्पादन क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए अपना खुद का ईंधन बनाने की जरूरत है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में शनिवार को भी 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो पांच दिनों में चौथी वृद्धि है। यह कहते हुए कि उच्चतम न्यायालय ने हिंदुत्व को जीवन का एक तरीका बताया है, गडकरी ने कहा कि धर्म और समुदाय एक-दूसरे से अलग हैं।

विद्युत मंत्रालय ने पर्याप्त कोयले की उपलब्धता हेतु समयबद्ध कार्यवाई करने के लिए परिपत्र जारी किया

नई दिल्ली (आरएनएस)। विद्युत मंत्रालय देश में कोयला आपूर्ति की स्थिति की निगरानी कर रहा है और उसने कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) और कैप्टिव कोयला खदानों से प्राप्त घरेलू कोयले के आधार पर पर्याप्त कोयला आपूर्ति और कोयला भंडार सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं।

राज्य जेनकोस, आईपीपी और सेंट्रल जेनकोस के परामर्श से बिजली मंत्रालय में लिए गए निर्णय के अनुसार, घरेलू कोयला आपूर्ति सभी जेनकोस के लिए सीआईएल/ एससीसीएल से प्राप्त कोयले की समानुपाती बनायी जाएगी और किसी भी कमी को पूरा करने के लिए समानुपातिक आधार के अतिरिक्त अन्य कोयला देना संभव नहीं होगा।।

विद्युत मंत्रालय ने घरेलू कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्रवाइयों को प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश देते हुए एक परिपत्र जारी किया है:-

बिजली संयंत्रों को आवंटित कैप्टिव कोयला खानों में उत्पादन कोयला मंत्रालय द्वारा अनुमत सीमा तक अधिकतम किया जा सकता है।

ऐसी रिपोर्ट की गई है कि कई बिजली संयंत्र रेलवे रैक से कोयले को उतारने में मानक से अधिक समय ले रहे हैं जो टर्न-अराउंड समय को प्रभावित कर रहा है। सीईए को बिजली संयंत्रों में उतराई के समय की निगरानी करने के लिए कहा गया है और यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे बिजली संयंत्रों को कम संख्या में रेक उपलब्ध कराए जाएं जहां रेक से कोयले की शीघ्र उतराई में ढिलाई बरती जा रही है। यह कदम उपलब्ध रेल रेकों का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसलिए इस पहलू की निगरानी राज्य सरकार के स्तर पर की जाए और कोयले की उतराई निर्धारित मानकों के भीतर सुनिश्चित की जाए।

कई उत्पादन कंपनियों पर कोयला कंपनियों का कई सौ करोड़ रुपये बकाया हैं। इतनी बड़ी बकाया राशि कोयला कंपनियों की कोयला आपूर्ति जारी रखने की क्षमता को प्रभावित करती है। अत: यह आवश्यक है कि कोयला कंपनियों के बिलों का भुगतान नियत समय पर किया जाए जिसके कि ऐसी उत्पादक कंपनियों को कोयले की आपूर्ति इस कारण प्रभावित न हो।

यह देखा गया है कि राज्यों में कुछ आयातित कोयला आधारित (आईसीबी) संयंत्रों के गैर-संचालन ने घरेलू कोयले की मांग पर अधिक दबाव डाला था जिससे घरेलू कोयला आधारित (डीसीबी) संयंत्रों के लिए कोयले का स्टॉक कम हो गया था।

खरीददार और विक्रेता, दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित पीपीए द्वारा कानूनी रूप से बाध्य हैं। जहां खरीददार पीपीए के अनुसार समय पर बिलों का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं, जेनकोस (विक्रेता) पर्याप्त ईंधन स्टॉक बनाए रखने और पीपीए के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं। पर्याप्त ईंधन स्टॉक नहीं रखना या किसी भी बहाने उपलब्धता सुनिश्चित न करना (जैसे आयातित कोयले की उच्च कीमत आदि) अक्षम्य माना जाएगा। विक्रेता की तरफ से इस तरह के आचरण का राज्य सरकार के स्तर पर सभी संभावित संविदात्मक और अन्य उपलब्ध कानूनी युक्तियों का उपयोग करके क्रेता द्वारा तुरंत सख्ती से प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। यदि विक्रेता की ओर से कोई धोखाधड़ी पायी जाती है जैसे कि पीपीए के तहत बिजली की आपूर्ति नहीं करना और बाजार में बिक्री करना, तो तत्काल हस्तक्षेप के लिए बिजली मंत्रालय को सूचित करते हुए बिना किसी देरी के इसे नियामकीय आयोग के संज्ञान में लाया जाना चाहिए।